समक्ष - मुकुल मुद्गल, सी.जे. और अजय तिवारी जे.,

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड - अपीलकर्ता

बनाम

पी.ओ. केंद्र सरकार, औद्योगिक न्यायाधिकरण और अन्य, - प्रतिवादी

LPA No. 221 0f 2006 in

CWP No. 1987 OF 1985

8 सितम्बर 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-तकनीकी नौकरियों पर कर्तव्य निभाने वाले कर्मचारियों से कार्य प्रभार-वेतनमान में संशोधन का दावा-औद्योगिक विवाद-न्यायाधिकरण द्वारा वेतनमान में संशोधन की अनुमति देना-न्यायाधिकरण के पुरस्कारों को एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखना-कार्यभारित कार्य के बीच सेवा शर्तों में अंतर और नियमित कर्मचारी - कार्य प्रभारित कर्मचारी जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है - नियमित और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने में कोई अंतर्निहित कमजोरी नहीं है - अपील की अनुमति, एकल न्यायाधीश और न्यायाधिकरण के निर्णयों को रद्द कर दिया गया, हालांकि, अपीलकर्ता को पहले से किए गए भुगतान की वसूली नहीं करने का निर्देश दिया गया काम करने वालों को.

अभिनिर्णित - 28 मई, 1970 का वह पत्र, जो पंजाब वेतन आयोग द्वारा बी.बी.एम.बी. द्वारा पूर्व-कैडर पदों की 'बची हुई' श्रेणियों के लिए संशोधित वेतनमान तैयार करने के कार्यान्वयन से संबंधित है, अपने आप में लागू नहीं माना जाएगा। . उक्त पत्र का अवलोकन वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा की गई व्याख्या की पुष्टि करता है कि उक्त पत्र केवल अपीलकर्ता के नियमित कर्मचारियों पर लागू होता है, न कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर। जहां तक एमडब्ल्यू 1 के बयान का संबंध है, उक्त स्वीकारोक्ति, जो कि उसकी अपनी राय हो सकती है, उसे कथित समानता का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, न तो ट्रिब्यूनल और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने कार्य प्रभारित कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों में अंतर पर विचार किया है। इन भिन्न सेवा शर्तों को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि नियमित कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने में कोई अंतर्निहित दुर्बलता नहीं हो सकती है।

(पैरा 7)

डी.एस. नेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एस. बावा, अधिवक्ता, अपीलकर्ता।

आर.एस. प्रतिवादी(ओं) की ओर से बैंस, अधिवक्ता

अजय तिवारी ज.

(1) यह आदेश एल.पी.ए. तय करेगा। 2006 की संख्या 221,224 और 225, क्योंकि वे 5 जुलाई, 2006 के न्यायालय के सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुए हैं। सुविधा के लिए, तथ्यों को 2006 की एल.पी.ए. संख्या 221 से लिया जा रहा है।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के कर्मचारी, जो फिटर/सहायक फोरमैन स्पेशल (वर्क-चार्ज) की श्रेणियों से संबंधित हैं और अत्यधिक कुशल और जटिल प्रकृति की तकनीकी नौकरियों पर कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने वेतनमान से असंतुष्ट हैं। अपने संबंधित वेतनमानों को संशोधित करने और ठीक करने की प्रार्थना करते हुए एक औद्योगिक विवाद उठाया। उपयुक्त सरकार ने उक्त विवादों को निर्णय के लिए पीठासीन अधिकारी, केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ को भेज दिया। ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रबंधन की दलील थी कि बीबीएमबी में काम करने वाले फिटरों को विभिन्न नौकरियों/वर्गीकरण/व्यापार पर तैनात किया गया है और उक्त कर्मियों को वेतनमान उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों/कार्यों की अवधि के अनुसार दिया गया है। प्रबंधन ने आगे दलील दी कि संबंधित श्रमिकों को रुपये के संशोधित वेतनमान में तय किया गया था। 110-180 उनके विकल्प प्राप्त करने के बाद, उस संबंध में लागू नियमों के अनुसार।

(3) ट्रिब्यूनल ने, 29 अगस्त, 1984 के अलग-अलग पुरस्कारों के माध्यम से, माना कि भले ही प्रबंधन ने श्रमिकों को रुपये के पैमाने पर फोरमैन स्पेशल (चयन ग्रेड) के बराबर करने से इनकार कर दिया था। 400-650, फिर भी उन्हें रुपये के समयमान से इनकार करने का कोई

तर्क नहीं था। 300-500. हालाँकि, सुनवाई के दौरान, यह ट्रिब्यूनल के ध्यान में लाया गया कि 1 जनवरी, 1978 से वेतनमान में एक और संशोधन हुआ था और परिणामस्वरूप, प्रबंधन को श्रमिकों को रुपये के वेतनमान में तय करने का निर्देश दिया गया था। . 1 फरवरी, 1968 से 300-500 और उन्हें 1 जनवरी, 1978 से दिए गए नए संगत वेतनमान में फिर से तय किया गया, लेकिन पिछले वेतन का दावा 31 दिसंबर, 1977 तक सीमित था।

(4) पुरस्कार से असंतुष्ट प्रबंधन ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। इस न्यायालय ने, 5 जुलाई, 2006 के एक सामान्य निर्णय के माध्यम से, ट्रिब्यूनल के पुरस्कारों को बरकरार रखा, इसलिए ये अपीलें हैं।

(5) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश ने यांत्रिक रूप से कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान को नियमित प्रतिष्ठान के बराबर करने में गलती की है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जिस पद के साथ समीकरण मांगा गया था वह किसी भी मामले में एक प्रमोशनल पद था और इस प्रकार, उत्तरदाताओं द्वारा कब्जा किए गए पदों के साथ कोई समानता नहीं हो सकती है। कार्य प्रभारित स्थापना और नियमित स्थापना के बीच अंतर्निहित अंतर के साक्ष्य के रूप में, निम्नलिखित बताया गया है: -

> “(i) नियमित कर्मियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाता है जबकि कार्य प्रभारित कर्मियों को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाता है।

(ii) कार्य प्रभारित कर्मियों को ईपीएफ लाभ मिल रहा है जबकि नियमित कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिल रहा है।

(iii) कार्य प्रभारित कर्मियों को वेतन +डीए के आधार पर अनुग्रह राशि और ग्रेच्युटी मिल रही है, जबकि नियमित कर्मचारियों को उसी आधार पर नहीं मिलती है। उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान केवल उस आधार पर किया जाता है जो कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को समान वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाली राशि का आधा हो जाता है।

(iv) कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को वेतन की दोगुनी दर पर ओवरटाइम मिल रहा है, जबकि नियमित कर्मचारियों को उनकी सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार यह बिल्कुल नहीं मिलता है।

(v) कार्य-प्रभारित कैडर में पदोन्नति के रास्ते खुले और विशाल हैं और एक साधारण ट्रेडमैन आसानी से फोरमैन स्पेशल (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नति की आकांक्षा कर सकता है, जबकि नियमित कैडर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है।

(6) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने जोरदार आग्रह किया है कि पत्र दिनांक 28 मई, 1970, पूर्व। W10, मामले को समाप्त करता है क्योंकि उस पत्र के द्वारा अपीलकर्ता ने स्वयं श्रमिकों के दावे को स्वीकार कर लिया था। उनके तर्क के अनुसार, इस स्पष्ट स्थिति को देखते हुए, अपीलकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए प्रश्न नहीं उठते हैं। उन्होंने एमडब्ल्यू 1 के

साक्ष्य पर भी भरोसा किया है जिन्होंने कथित तौर पर उत्तरदाताओं के मामले को स्वीकार कर लिया था।

(7) पहले उत्तरदाताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटने के लिए, हमने 28 मई, 1970 के पत्र का अवलोकन किया है जो पंजाब वेतन आयोग द्वारा पूर्व की 'बची हुई' श्रेणियों के लिए संशोधित वेतनमान तैयार करने के कार्यान्वयन से संबंधित है। बी.बी.एम.बी. द्वारा कैडर पोस्ट हमारी सुविचारित राय में, यह पत्र अपने आप में प्रथम दृष्टया लागू नहीं माना जाएगा। अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, उक्त पत्र केवल नियमित कर्मचारियों से संबंधित था। इसका अवलोकन वास्तव में अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई व्याख्या की पुष्टि करता है कि उक्त पत्र केवल अपीलकर्ता के नियमित कर्मचारियों पर लागू होता है, न कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर। जहां तक एम डब्ल्यू 1 के बयान का संबंध है, उक्त स्वीकारोक्ति, जो कि उनकी अपनी राय हो सकती है, को कथित समानता का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है, इसके अलावा, हम पाते हैं कि न तो ट्रिब्यूनल और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पर विचार किया है कार्य प्रभारित कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों में अंतर, जैसा कि ऊपर बताया गया है। हमारी राय में, इन भिन्न सेवा शर्तों को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि नियमित कर्मचारियों और कार्य प्रभारित स्टॉल के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने में कोई अंतर्निहित दुर्बलता नहीं हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, दावा आवेदन के लिखित विवरण के पैराग्राफ 2 में, इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है: -

> "2. पैरा 2 को इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि वर्कचार्ज सहायक। फोरमैन स्पेशल शुरू में मशीनों के रूप में काम कर रहे थे। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, चार्जसीएमसीएन। भाखड़ा बांध के निर्माण के दौरान चार्जमेन स्पेशल। बाद में उन्हें सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया। फ़ोरमैन स्पेशल इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से कोई भी तकनीकी रूप से योग्य नहीं था और उनमें से अधिकांश मैट्रिक से कम और शायद ही कभी मिडिल पास थे।

(8) उसकी प्रतिकृति में, उत्तरदाताओं ने इस प्रकार उल्लेख किया है: -

> "2. प्रबंधन का लिखित बयान इस हद तक स्वीकार किया गया है कि सहायक फोरमैन एसपीपी अपने अच्छे काम के कारण विभिन्न निचली श्रेणी से उत्पन्न हुए हैं। बाकी पैरा अप्रासंगिक है।"

(9) इस प्रकार, उत्तरदाताओं ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का अभाव है।

(10) राजस्थान राज्य बनाम कुंजी रमन[1] में, (1) प्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:-

"8, इस प्रकार एक कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान एक नियमित प्रतिष्ठान से भिन्न होता है जो प्रकृति में स्थायी होता है। की स्थापना और (आई) एआईआर 1997 एस.सी. 693 किसी कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान की निरंतरता सरकार द्वारा एक परियोजना या एक योजना या एक 'कार्य' शुरू करने और इसे क्रियान्वित करने के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जहां तक कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारियों का सवाल है, न केवल उनकी भर्ती और सेवा शर्तें, बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और कर्तव्य भी नियमित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के समान नहीं हैं। **एक नियमित प्रतिष्ठान और एक कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान दो अलग-अलग प्रकार के प्रतिष्ठान हैं और उन प्रतिष्ठानों पर कार्यरत व्यक्ति इस प्रकार दो अलग और विशिष्ट वर्ग बनाते हैं।** इस कारण से, यदि कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान पर लगे व्यक्तियों के लिए नियमों का एक अलग सेट बनाया गया है और नियमित प्रतिष्ठान पर काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू होने वाले सामान्य नियम उन पर लागू नहीं किए जाते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। सरकार द्वारा मनमाना और भेदभावपूर्ण तरीका। यह सर्वविदित है कि सरकार के पास विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग

[1] AIR 1997 SC 693

नियम बनाने की शक्ति है। इसलिए, हम 1993 की सिविल अपील संख्या 653 में अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद को खारिज करते हैं कि आरएसआर के नियम के खंड (जी), (एच) और (आई) संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं और कायम रखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण।" (जोर दिया गया)

(11) ऊपर दिए गए कारणों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील के साथ-साथ संबंधित अपीलों, विद्वान एकल न्यायाधीश और न्यायाधिकरण के निर्णयों की अनुमति दी जाती है। खारिज कर दिया जाता है और उत्तरदाताओं का दावा खारिज कर दिया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(12) हमें सूचित किया गया है कि विवादित पुरस्कारों के तहत श्रमिकों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में कानून की स्थिति स्पष्ट करते हुए भी यह निर्देशित किया जाता है कि पहले से किये गये भुगतान की वसूली श्रमिकों से नहीं की जायेगी। हालाँकि, इस निर्णय के संदर्भ में, किसी भी अन्य परिणामी लाभ से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)